प्रेस विज्ञप्ति

11 अप्रैल, 2017

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला, मीडिया प्रभारी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने निम्नलिखित बयान जारी किया :–

''नए बिजली कनेक्शनों के लिए सिक्योरिटी राशि, सर्विस कनेक्शन चार्जेस व एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फीस में की गई भारी बढ़ोत्तरी वापस हो''

''चोर दरवाजे से की गई भारी बढ़ोत्तरी है, खट्टर सरकार का जजिया कर''

हरियाणा की भाजपा सरकार द्वारा नए घरेलू कनेक्शन के लिए की गई अघोषित बढ़ोत्तरी, जनता के साथ धोखा व खून पसीने की कमाई में लूट है। नए घरेलू बिजली कनेक्शन के लिए सरकार ने चोर दरवाजे से सिक्योरिटी राशि, सर्विस कनेक्शन चार्जेस व एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फीस सहित पांच मदों में भारी बढ़ोत्तरी करते हुए नया घरेलू बिजली कनेक्शन 725 रु. महंगा कर दिया है। आश्चर्यजनक बात यह है कि बिजली दरों में बढ़ोत्तरी 5 अप्रैल, 2017 को गुपचुप तरीके से दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम द्वारा जारी एक पत्र के जरिए की गई है और इसे 19 जुलाई, 2016 से लागू भी कर दिया गया है, जिसके चलते पिछले नौ महीने में बिजली कनेक्शन लेने वाले उपभोक्ताओं से रिकवरी की जाएगी और उन्हें बढ़ी हुई दरों के अनुसार राशि भरनी होगी।

एक तरफ तो खट्टर सरकार बिजली दरों में कटौती की बड़ी–बड़ी घोषणाएं कर रही है, और दूसरी तरफ आम जनता व बिजली उपभोक्ताओं पर आर्थिक बोझ लादती जा रही है। नया कनेक्शन लेते समय भरी जाने वाली सिक्योरिटी राशि को खट्टर सरकार ने 50% तक बढ़ा दिया है। गैर घरेलू उपभोक्ताओं से वसूला जाने वाला सर्विस कनेक्शन चार्ज अब सरकार द्वारा घरेलू उपभोक्ताओं से भी वसूला जाएगा, जिससे यह बोझ प्रदेश की आम जनता पर पड़ेगा। नया कनेक्शन लेने वाले घरेलू उपभोक्ताओं से अब 200 से 1000 रु. तक सर्विस कनेक्शन चार्जेस के रूप में भी वसूले जाएंगे। पहले घरेलू उपभोक्ताओं से यह राशि नहीं ली जाती थी। अब सिंगल फेज़ 2 किलोवॉट तक के घरेलू कनेक्शन के लिए 200 रु., 2 किलोवॉट से अधिक लोड के लिए 500 रु. व 3 फेज़ कनेक्शन के लिए 1000 रु. बिजली निगमों द्वारा सर्विस कनेक्शन चार्जेस के रूप में वसूले जाएंगे। बिजली सिक्योरिटी में भी घरेलू कनेक्शन के लिए जमा की जाने वाली सिक्योरिटी राशि को 500 रु. प्रति किलोवाट से बढ़ाकर 750 रु. प्रतिकिलोवाट कर दिया गया है। इसी प्रकार एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फीस को भी दोगुना करते हुए 2 किलोवॉट के लिए 50 रु. कर दिया गया है।

प्रदेश की खट्टर सरकार जनता को कोई राहत देने की बजाए उन पर नए–नए तरीकों से आर्थिक बोझ लादती जा रही है। भाजपा की सरकार बनने के बाद, पेट्रोल व डीज़ल पर वैट में भारी वृद्धि की गई है। पहले पेट्रोल पर 21% व डीज़ल पर 9.24% वैट लगता था, जिसे खट्टर सरकार पहले ही क्रमशः 26.25% तथा 17.22% कर चुकी है।